

प्रारंभिक परीक्षा

RBI के तरलता इंजेक्शन उपाय

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च 2025 के सेकंड हाफ के दौरान बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षित तरलता की तंगी को कम करने के लिए ₹1.87 लाख करोड़ के तरलता इंजेक्शन उपायों की घोषणा की है।

प्रमुख उपायों की घोषणा -

- खुले बाजार परिचालन (OMO) सरकारी प्रतिभूतियों (G-SECS) की खरीद
 - o RBI 50,000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में OMO खरीद करेगा।
- USD/INR खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी:
 - o RBI 10 बिलियन डॉलर मूल्य की USD/INR खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा
 - अवधि: तीन साल

तरलता इंजेक्शन के पीछे तर्क -

- बैंकिंग प्रणाली से आगामी बहिर्वाह:
 - अग्रिम कर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान के कारण मार्च 2025 के मध्य से लगभग
 ₹2.50 लाख करोड़ की तरलता तंगी की उम्मीद है।
- विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करना और रुपया-डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करना।
- जनवरी-फरवरी 2025 में पिछले हस्तक्षेपों के बाद आरबीआई के तरलता समर्थन उपायों को जारी रखना।

खुले बाजार परिचालन (OMO) के बारे में -

- खुले बाजार परिचालन(OMO) से तात्पर्य बैंकिंग प्रणाली में तरलता को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-SECS) की खरीद और बिक्री से है।
- OMO कैसे काम करता है?
 - OMO खरीद → RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है → बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता → ब्याज दरें गिरती हैं → ऋण सस्ते होते हैं → निवेश और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।
 - तरलता बढ़ने से शेयर बाजार को लाभ होता है।
 - OMO बिक्री → RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है → तरलता कम करता है → बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होता है → ब्याज दरें बढ़ती हैं → ऋण महंगे हो जाते हैं → मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है।
 - तरलता कम होने के कारण शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि 'स्टरलाइजेशन' का हिस्सा मानी जाती है? (2023)

- (a) 'खुले बाजा्र परिचालन' का संचालन
- (b) निपटान और भुगतान प्रणालियों की निग्रानी
- (c) केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ऋण और नकदी प्रबंधन
- (d) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का विनियमन

उत्तर:(a)

स्रोत: The Hindu - Reserve Bank to buy ₹1 lakh crore G-Secs



विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2025

संदर्भ

हाल ही में TERI द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2025 का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय था "सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी।"

विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (WSDS) के बारे में -

- WSDS एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो स्थिरता, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण नीतियों पर केंद्रित है।
- इसका **आयोजन प्रतिवर्ष ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) द्वारा** किया जाता है।
- यह शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों और नागरिक समाज को पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करने और समाधान विकसित करने के लिए एक साथ लाता है।
- WSDS के मुख्य उद्देश्य:
 - सतत विकास को बढ़ावा देना ऐसी नीतियों और कार्यों को प्रोत्साहित करना जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करें।
 - जलवायु कार्रवाई एवं नीति चर्चाएँ साझेदारी और नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से वैश्विक जलवायु चुनौतियों का समाधान करना।
 - उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटना यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों (वैश्विक दक्षिण) की जलवायु वार्ताओं में मजबूत आवाज हो।

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI)

- ऊर्जा और संसाधन संस्थान(TERI) भारत में एक शोध एवं नीति थिंक टैंक है जो टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए काम करता है।
- इसकी स्थापना 1974 में टाटा समूह द्वारा की गई थी।
- **फोकस क्षेत्र:** सतत विकास, जलवायुँ परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और हरित प्रौद्योगिकियां। **TERI द्वारा प्रमुख पहल:**
 - WSDS (विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन) स्थिरता पर वार्षिक वैश्विक आयोजन।
 - TERI स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (TERI एसएएस) पर्यावरण और स्थिरता अध्ययन पर केंद्रित शैक्षणिक संस्थान।
 - **लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स (एलएबीएल)** ग्रामीण भारत में **सौर प्रकाश व्यवस्था को** बढ़ावा देने की पहल।
 - गृहं (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग) सतत वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए एक हरित भवन प्रमाणन प्रणाली।

स्रोत: PIB - WSDS



पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 और 2025-26 के लिए 3,880 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी दी।

पश्धन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के बारे में -

- LHDCP एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य टीकाकरण, रोग नियंत्रण और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे में वृद्धि के माध्यम से पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- **कवर किए गए रोग:** खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी), एंथ्रेक्स, रेबीज और अन्य पशुधन रोग।

कार्यक्रम के प्रमुख घटक -

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP):
 - o **लक्षित रोग:** खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस
 - o **लक्ष्य:** मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों के लिए 100% टीकाकरण कवरेज।
 - । 2030 तक एफएमडी और ब्रुसेलोसिंस का उन्मूलन।
- गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP): 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) को लक्षित करता है।
- मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVU): निदान और उपचार सुविधाओं के साथ अनुकूलित वाहनों के माध्यम से घर-द्वार पर पशु चिकित्सा देखभाल।
- पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD): राज्य-प्राथमिकता वाले विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों को लक्षित करना, जिसमें लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) भी शामिल है।
- पशु औषि: यह पीएम-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी सिमितियों के नेटवर्क के माध्यम से जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए योजना में जोड़ा गया एक नया घटक है।

स्रोत: <u>The Hindu - LHDCP</u>



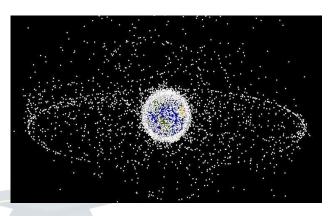
अंतरिक्ष मलबा और संबंधित मुद्दे

संदर्भ

अंतरिक्ष में बढ़ती गतिविधियों के साथ, अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले मलबे की समस्या एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून में खामियों के कारण ऐसे मलबे के लिए जवाबदेही अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है।

अंतरिक्ष मलबे के बारे में -

- अंतिरक्ष मलबा, जिसे अंतिरक्ष कबाड़ के नाम से भी जाना जाता है, मानव निर्मित उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जो अब परिचालन योग्य नहीं हैं और पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं।
- इन वस्तुओं में नष्ट हो चुके उपग्रह, रॉकेट के नष्ट हो चुके चरण, अंतरिक्ष यान की टक्करों के टुकड़े तथा पिछले अंतरिक्ष मिशनों से निकले अन्य बेकार पड़े हार्डवेयर शामिल हैं।



अंतरिक्ष मलबे की जवाबदेही के लिए कानूनी ढांचा -

- बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967):
 - अनुच्छेद VI: राज्य अपनी सरकारों या निजी संस्थाओं द्वारा संचालित सभी अंतिरक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे।
- अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षित के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन (1972):
 - पृथ्वी पर अंतिरक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली क्षिति के लिए "पूर्ण उत्तरदायित्व" स्थापित किया
 गया है।
 - मुख्य मुद्दाः यदि मलबा राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा, तो जवाबदेही लागू करना कठिन हो जाएगा।
 - उदाहरण के लिए
 - 1978 सोवियत उपग्रह कॉस्मोस 954 कनाडा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
 - कनाडा ने सोवियत संघ के साथ वर्षों तक बातचीत की और 6 मिलियन डॉलर की सफाई लागत में से केवल 3 मिलियन डॉलर ही प्राप्त कर सका।

प्रमुख अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) और मलबा शमन पहल -

- प्रोजेक्ट नेत्र इसरो:
 - यह भारतीय उपग्रहों के मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतिरक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है।
 - एक बार चालू हो जाने पर, यह भारत को अन्य अंतिरक्ष शक्तियों की तरह एसएसए में अपनी क्षमता प्रदान करेगा।
 - नेत्र 10 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं को, 3,400 किमी की दूरी तक तथा लगभग 2,000 किमी की अंतरिक्ष कक्षा के बराबर वस्तुओं को खोज, ट्रैक और सूचीबद्ध कर सकता है।
- इसरो की सुरक्षित एवं सतत अंतरिक्ष परिचालन प्रबंधन प्रणाली (IS40M):
 - यह इसरो की एक पहल है जो अंतिरक्ष में सुरिक्षत और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
 - कार्यः कक्षीय क्षय की निगरानी, अंतिरक्ष मलबे का प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग



अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय सिमिति (IADC):

- यह 1993 में स्थापित एक अंतर-सरकारी मंच है जिसका उद्देश्य अंतिरक्ष मलबे के मुद्दों के समाधान के प्रयासों का समन्वय करना है।
- आईएडीसी के सदस्य: नासा (यूएसए), ईएसए (यूरोपीय अंतिरक्ष एजेंसी), इसरो (भारत), सीएनएसए (चीन राष्ट्रीय अंतिरक्ष प्रशासन), जेएक्सए (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी)

सक्रिय मलबा हटाने (ADR) प्रौद्योगिकियां -

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) क्लियरस्पेस-1 मिशन (2026)
 - विश्व का पहला अंतिरक्ष मलबा हटाने का मिशन।
 - इसका उद्देश्य रोबोटिक भुजाओं का उपयोग करके एक निष्क्रिय वेस्पा पेलोड एडाप्टर (~ 100 किग्रा) को पकड़ना और उसे कक्षा से हटाना है।
- नासा का OSAM-1 (ऑन-ऑर्बिट सर्विसिंग, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग):
 - उपग्रहों की जीवन अविध बढ़ाने और मलबे को कम करने के लिए उनकी रोबोटिक सर्विसिंग पर काम किया जा रहा है।
- जापान का एस्ट्रोस्केल ELSA-d मिशन:
 - निष्क्रिय उपग्रहों को पकड़ने और हटाने के लिए चुंबकीय डॉकिंग प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना।
 - इसका उद्देश्य वाणिज्यिक मलबा हटाने की सेवाएँ विकसित करना है।
- चीन की अंतरिक्ष मलबा हटाने की परियोजनाएं:
 - शिजियान-21 उपग्रह के साथ परीक्षण किया गया, जिसके माध्यम से एक निष्क्रिय उपग्रह को सफलतापूर्वक कब्रिस्तान की कक्षा में पहुंचाया गया।





ट्रम्प की गाजा योजना का मिस्र द्वारा विकल्प

संदर्भ

हाल ही में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के बाद गाजा में उत्पन्न मानवीय संकट पर विचार करने के लिए अरब लीग द्वारा काहिरा, मिस्र में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।

गाजा पर काहिरा घोषणा - 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना -

- काहिरा घोषणापत्र में गाजा के लिए मिस्र के नेतृत्व वाली 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को अपनाया गया।
- इसमें अरब देशों से राजनीतिक, वित्तीय और भौतिक सहायता शामिल है।
- यह युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला प्रमुख अरब प्रस्ताव है, जो पूर्ण युद्धिवराम पर निर्भर है।

काहिरा घोषणा के प्रमुख तत्व -

- गाजा के लिए शासन और राजनीतिक संरचना:
 - घोषणापत्र में एक संक्रमणकालीन अविध के लिए योग्य गाजावासियों वाली "गाजा प्रशासन सिमिति" के गठन का आह्वान किया गया है।
 - इस अंतिरम प्रशासन का उद्देश्य गाजा पर शासन करने और चुनाव कराने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) की वापसी की तैयारी करना है।
 - घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से हमास या उसके निष्कासन का उल्लेख नहीं किया गया है , जिसकी इजरायल और अमेरिका ने आलोचना की थी।
- गाजा और पश्चिमी तट में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एवं सुरक्षाः
 - यह बहरीन घोषणा (मई 2024) को दोहराता है जिसमें निम्नलिखित का आह्वान किया गया है:
 गाजा और पश्चिमी तट दोनों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती।
- द्वि-राज्य समाधान एवं फिलिस्तीनी संप्रभुताः
 - यह 2002 की अरब शांति पहल और दो-राज्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
 - 1967 से पहले की सीमाओं के भीतर एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की मांग करता है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम होगी।
 - यह इस बात पर जोर देता है कि इजरायल की संप्रभुता की अरब मान्यता फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर निर्भर है।
- पुनर्निर्माण के लिए ट्रस्ट फंड:
 - गाजा की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण पिरयोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक "ट्रस्ट फंड" की स्थापना।
- फ़िलिस्तीनी राजनीतिक एकताः
 - घोषणापत्र में सभी फिलिस्तीनी गुटों से आवश्यक सुधारों के बाद फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) के तहत एकजुट होने का आह्वान किया गया है।
 - PLO (जिसमें फतह भी शामिल है) को फिलिस्तीनी लोगों का "एकमात्र वैध प्रतिनिधि" माना गया है।
 - हमास PLO का हिस्सा नहीं है।

स्रोत: Indian Express - Egyptian alternative to Trump's Gaza plan



अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा(Antarctic Circumpolar Current)

संदर्भ

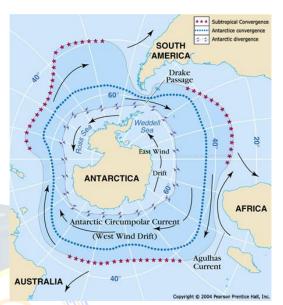
मेलबर्न विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य में 2050 तक अंटार्कटिक परिध्रवीय धारा(ACC) 20% तक कमजोर हो सकती है।

अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा (ACC) के बारे में -

- यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में बहती है।
- यह अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों को जोडती है।
- यह गल्फ स्ट्रीम से चार गुना अधिक शक्तिशाली है, जो प्रति सेकंड लगभग 165 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का परिवहन करती है।

महत्व:

- समुद्र में गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को नियंत्रित करती है।
- यह गर्म पानी को अंटार्किटिका तक पहुंचने से रोकती है, जिससे हिम चादरें सुरक्षित रहती हैं।
- अन्य महाद्वीपों से अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली आक्रामक प्रजातियों (जैसे, बुल केल्प, झींगा, मोलस्क) को रोकती है।



ACC के कमजोर होने के कारण -

- महासागरीय लवणता में परिवर्तन: अंटार्कटिका के आसपास बर्फ की चट्टानों के तेजी से पिघलने (ग्लोबल वार्मिंग के कारण) के कारण अंटार्कटिका का निचला जल (AABW) कमजोर हो गया है।
 - AABW एक डूबने वाली प्रक्रिया है और वैश्विक महासागर परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो ACC के परिसंचरण से जुड़ा हुआ है।
- बढ़ता वैश्विक तापमान: गर्म तापमान से वायु पैटर्न में पिरवर्तन होता है जो ACC को चलाता है।

कमज़ोर ACC के संभावित प्रभाव -

- अधिक चरम मौसम और जलवायु अस्थिरताः
 - ACC वैश्विक पवन और मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है।
 - कमजोर ACC के कारण दुनिया भर में शक्तिशाली तूफान, हीटवेव और चरम जलवायु घटनाएं हो सकती हैं।

• वैश्विक तापमान में वृद्धिः

- महासागर ग्रीनहाउस गैसों द्वारा फँसी हुई अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग 90% अवशोषित कर लेते हैं।
- यदि ACC कमजोर हो जाए, तो महासागर की ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आएगी।
- समुद्र का बढ़ता स्तर एवं बर्फ की चादर का पिघलना:
 - ACC गर्म पानी को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती है।



 यदि यह कमजोर पड़ता है, तो गर्म महासागरीय धाराएं अंटार्कटिका की बर्फ को नष्ट कर देंगी, जिससे समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ेगा।

• महासागरीय परिसंचरण में व्यवधान:

- ACC वैश्विक महासागर धाराओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) भी शामिल है।
- मंदी से प्रमुख समुद्री धाराएं कमजोर हो सकती हैं, जिससे वर्षा, मानसून और कृषि पैटर्न बाधित हो सकते हैं।

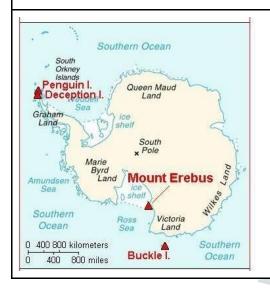
स्रोत: NDTV - Earth's strongest ocean current





समाचार में स्थान

माउंट एरेबस



- अवस्थिति: रॉस द्वीप, अंटार्कटिका।
- यह पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है।
- इसकी खोज 1841 में ब्रिटिश खोजकर्ता सर जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी, तथा इसका नाम उनके जहाज एचएमएस एरेबस के नाम पर रखा गया।
- इसमें एक सक्रिय लावा झील है।
- यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जो प्रशांत महासागर बेसिन को घेरता है।
- यह महाद्वीप पर केवल दो सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है; डिसेप्शन द्वीप दूसरा है।

स्रोत: Mount Erebus





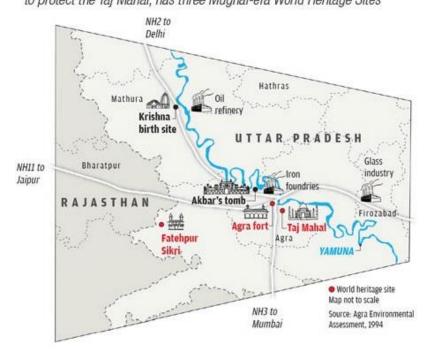
समाचार संक्षेप में

ताज ट्रेपेज़ियम जोन

 सर्वोच्च न्यायालय ने वन अनुसंधान संस्थान (FRI) को ताज ट्रेपेज़ियम जोन में वृक्षों की गणना करने का निर्देश दिया है।

ताज ट्रेपेज़ियम जोन (TTZ) के बारे में -

- TTZ ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर का निर्धारित क्षेत्र है।
- इसमें तीन विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं: ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी।
- यह उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान में भरतपुर जिले तक फैला हुआ है।
- उद्देश्यः प्रदूषण को नियंत्रित करना और ताजमहल को पर्यावरणीय क्षरण से बचाना।
- केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत "ताज ट्रेपेज़ियम जोन प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण" का गठन किया है।
- TTZ में चार जोन हैं जिन्हें रेड, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट नाम दिया गया है।
 The 10,400 sq km Taj Trapezium Zone, which was demarcated in 1983 to protect the Taj Mahal, has three Mughal-era World Heritage Sites



स्रोत: <u>Indian Express - TTZ</u>

स्वावलंबिनी - महिला उद्यमिता कार्यक्रम

 हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय(MSDE) ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी कार्यक्रम शुरू िकया है।

स्वावलंबिनी के बारे में -

यह उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में युवा मिलाओं के लिए एक संरचित उद्यमिता पहल है।



- यह कौशल विकास, मेंटरशिप, वित्त पोषण सहायता और इनक्यूबेशन अवसर प्रदान करती है।
- **नोडल मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
- कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) और नीति आयोग।

स्वावलंबिनी कार्यक्रम के उद्देश्य

- संरचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना।
- स्थायी व्यवसाय स्थापित करने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- संकाय प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता शिक्षा को बढावा देना।
- को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय उनके नेतृत्व वाली विकास पहलों को प्रोत्साहित करना।

स्रोत: PIB - Swavalambini

आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायत पहल

• पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में 'मॉडल महिला-अनुकूल ग्राम पंचायत'(MWFGP) पहल शुरू की है।

पहल के बारे में -

 यह एक लैंगिक रूप से समावेशी शासन पहल है जिसे जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और नेतृत्व को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पहल की मुख्य विशेषताएं -

- आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायतों का शुभारंभः
 - 770 आदर्श मिहला-अनुकूल ग्राम पंचायतें विकसित की जाएंगी (प्रत्येक जिले में एक)।
 - ग्रामीण शासन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए आदर्श मॉडल के रूप में काम करेंगी।
- वास्तविक समय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया:
 - आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायतों की प्रगित पर नज़र रखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
 - जमीनी स्तर पर महिंलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए वास्तविक समय की जानकारी, डेटा विश्लेषण और हस्तक्षेप रणनीति प्रदान करेगा।
- ग्राम पंचायतों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम:
 - इसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर महिला नेताओं को प्रभावी शासन और महिला-केंद्रित नीति निर्माण के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है।

स्रोत: PIB - Model women friendly panchayats



संपादकीय सारांश

हिमालयवासियों से कौन माफ़ी मांगेगा?

संदर्भ

हाल ही में, नॉर्वे की संसद ने **सामी**, **क्वेन** और **फॉरेस्ट फिन** लोगों को लक्षित करने वाली अपनी समावेशन नीतियों (जिसे **नॉर्वेइज़ेशन** के रूप में जाना जाता है) के लिए औपचारिक माफ़ी मांगी।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- माफी के साथ-साथ, सरकार ने जारी भेदभाव को दूर करने के लिए उपाय प्रस्तावित किए, जैसे कि स्वदेशी भाषाओं की रक्षा करना और 2027 से शुरू होने वाले समावेशन प्रयासों की निगरानी करना।
- नॉर्डिक लोगों की तरह हिमालयी समुदायों को भी स्वदेशी संस्कृति और संसाधनों के दमन का सामना करना पड़ा।

भारत में हिमालयी समुदायों द्वारा सामना किया जा रहा दमन -

- संसाधनों का औपनिवेशिक शोषण: अंग्रेजों ने व्यापार और वन कानून लागू किये जिससे पारंपरिक आजीविका बाधित हुई।
 - रेलवे निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई (उदाहरण के लिए, रेलवे स्लीपरों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के साल के जंगलों को नष्ट कर दिया गया)।
 - व्यापार नाकेबंदी (जैसे, 1874 की नाकेबंदी ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को बाधित कर दिया)।
- स्वतंत्रता के बाद संसाधनों का दोहन: आदिवासियों के प्रति नेहरू के मानवतावादी दृष्टिकोण के बावजूद, बाद की पंचवर्षीय योजनाओं (5वीं और 6वीं) में संसाधनों के दोहन को प्राथमिकता दी गई।
 - जलविद्युत परियोजनाओं और वनों की कटाई के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ।
- स्वदेशी संस्कृति और पहचान का क्षरणः नीतियों ने आदिवासी पहचान को संरक्षित करने के बजाय आत्मसात करने का पक्ष लिया।

स्थान	जनजाति
हिमाचल प्रदेश	गद्दी किन्नौरा
सिक्किम	लेप्चा
सिक्किम और लद्दाख	भूटिया
	मोन
अरुणाचल प्रदेश	अबोर
	अका
	अपातानी
	मिश्मी
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल	खास
पाकिस्तान	कलश

- समय के साथ स्वदेशी भाषाएं और पारंपिरक शासन प्रणालियां कमजोर होती गईं।
- जलविद्युत विकास एवं भूमि हड़पना: बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के पक्ष में जनजातीय समुदायों के पारंपरिक भूमि अधिकारों की अनदेखी की गई।
 - नौकरशाही और कॉर्पोरेट गठजोड़ ने उचित परामर्श के बिना भूमि अधिग्रहण को आसान बना दिया।
 - उदाहरण: सामुदायिक प्रतिरोध के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढाना।



- पर्यटन-प्रेरित आर्थिक दबाव: प्राथमिक राजस्व स्रोत के रूप में पर्यटन की ओर बदलाव से संस्कृति का वस्तुकरण हुआ।
 - बढ़ते प्रवासन और भूमि अतिक्रमण ने स्थानीय आबादी को प्रभावित किया।
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपेक्षाः नीति निर्माण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं परामर्श का अभाव।
 - स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कनेक्टिविटी में बुनियादी ढांचे के अंतर ने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को और बदतर बना दिया है।

भारत के लिए नॉर्वे से सीख -

- ऐतिहासिक अन्याय के लिए स्वीकृति और क्षमा: भारत को औपनिवेशिक शोषण, स्वतंत्रता के बाद संसाधन निष्कर्षण और जबरन समावेशन के कारण हिमालयी जनजातियों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए।
- स्वदेशी भाषाओं और संस्कृति का संरक्षण एवं पुनरुद्धार: भारत को हिमालयी क्षेत्र में लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं, परंपराओं और शासन प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए मजबूत नीतियों को लागू करना चाहिए।
- भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए कानूनी सुरक्षाः भारत को जलविद्युत और पर्यटन-प्रेरित भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए जनजातीय भूमि अधिकारों और प्रथागत कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए।
- विकास और स्थिरता में संतुलन: भारत को शोषक विकास मॉडल से हटकर ऐसे मॉडल को अपनाना चाहिए जिसमें पारिस्थितिकी संरक्षण और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों को प्राथमिकता दी जाए।
- स्वदेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितं करनाः भारत को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने वाले निकायों में हिमालयी जनजातीय समुदायों का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितं करना चाहिए।
 - उदाहरण के लिए, नॉर्वे में स्वदेशी समुदायों को राजनीतिक आवाज देने के लिए सामी संसद है।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना:** भारत को मौजूदा असमानताओं को पाटने के लिए हिमालयी जनजातियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में निवेश करना चाहिए।

स्रोत: The Hindu: Who will apologise to the 'Himalayans'?



डीपसीक के बाजार में उथल-पुथल से भारत को जागना चाहिए

संदर्भ

चीन की कंपनी डीपसीक ने अपने कम लागत वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल से वैश्विक तकनीकी उद्योग और शेयर बाजारों में हलचल मचा दी है।

डीपसीक एआई के बारे में -

- इसकी स्थापना मई 2023 में लियांग वेनफ़ेंग द्वारा की गई थी और 2025 की शुरुआत में अपने डीपसीक-आर1 मॉडल के रिलीज़ के साथ यह व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया।
- डीपसीक एआई की विशेषताएं:
 - मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स (MoE) आर्किटेक्चर: पारंपिरक AI मॉडल के विपरीत, MoE यह सुनिश्चित करता है कि मॉडल के मापदंडों का केवल एक छोटा हिस्सा किसी भी समय सक्रिय हो।
 - इससे उच्च दक्षता बनाए रखते हुए कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता कम हो जाती है।
 - इससे तेजी से सीखने और समय के साथ बेहतर प्रदर्शन में भी मदद मिलती है।
 - बिना किसी सीमा के उपयोग हेतु निःशुल्कः
 - चैटजीपीटी की प्रीमियम सुविधाओं के विपरीत, डीपसीक एआई नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है।
 - दैनिक उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं, जिससे यह सभी के लिए सुलभ है।
 - लागत प्रभावी API मूल्य निर्धारण:
 - डीपसीक एआई, ओपनएआई के चैटजीपीटी की तुलना में काफी सस्ते एपीआई प्रदान करता है, जिससे यह डेवलपर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।
 - वास्तविक समय वेब खोज क्षमता: उपयोगकर्ता वास्तविक समय, अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए डीपसीक एआई से सीधे वेब खोज सकते हैं।

भारत के आईटी प्रभुत्व पर डीपसीक के नवाचार का प्रभाव -

- कम लागत वाले आईटी मॉडल में व्यवधान: भारत का आईटी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कुशल, लागत प्रभावी श्रम की प्रचुर आपूर्ति पर फलता-फूलता रहा है।
 - डीपसीक का एआई-संचालित स्वचालन मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करता है, जिससे आईटी सेवाओं में भारत की बढ़त को खतरा पैदा हो रहा है।
- एआई कौशल और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करता है: डीपसीक जैसे जनरेटिव एआई मॉडल भारत में परंपरागत रूप से आउटसोर्स किए जाने वाले कार्यों को कर सकते हैं, जैसे ग्राहक सहायता, कोडिंग और डेटा विश्लेषण।
 - ्र इ्ससे अंग्रेजी दक्षता और आईटी सेवाओं में भारत की बढ़त कम हो गई है।
- एआई और अनुसंधान एवं विकास निवेश में भारत पीछे: डीपसीक की सफलता एआई और कम्प्यूटेशनल क्षमताओं में चीन के मजबूत निवेश को दर्शाती है।
 - भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1% से कम है, जो चीन के 2.43% से काफी पीछे है, जिससे इसकी नवप्रवर्तन क्षमता प्रभावित हो रही है।
- श्रम-आधारित विकास से आगे बढ़ने की आवश्यकता: भारतीय आईटी फर्मों को श्रम-प्रधान मॉडल से एआई-संचालित समाधानों की ओर स्थानांतिरत होना होगा।
 - अनुकूलन में विफल रहने से भारत की आईटी सेवाओं की वैश्विक मांग कम हो सकती है।

डीपसीक से मुख्य सीखें -

 रणनीतिक निवेश के रूप में अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देना: डीपसीक की सफलता निरंतर एआई अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता को उजागर करती है, भले ही यह कंपनी का मुख्य व्यवसाय न हो। भारतीय आईटी फर्मों को दीर्घकालिक तकनीकी प्रगति में निवेश करना चाहिए।



- नवाचार के लिए निष्क्रिय पूंजी का उपयोग: कंपनियों को केवल कार्यबल अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिशेष संसाधनों को एआई और उभरती हुई तकनीक अनुसंधान में लगाना चाहिए।
- जोखिम उठाने और प्रयोग को प्रोत्साहित करना: डीपसींक ने एआई को एक गौण पहल के रूप में माना, फिर भी उसे अभूतपूर्व सफलता मिली। भारतीय फर्मों को ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ प्रयोग और विफलता को नवाचार की ओर कदम के रूप में देखा जाए।
- ऐसे कार्यबल का निर्माण करना जो AI के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं: AI का विरोध करने के बजाय, भारत को अपने कार्यबल को AI उपकरणों और स्वचालन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
- एआई और क्वांटम क्षमताओं का विकास: भारत को तकनीकी प्रगति की अगली लहर में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में आक्रामक रूप से निवेश करना चाहिए।

स्रोत: The Hindu: DeepSeek's market disruption must awaken India





रूस-यूक्रेन युद्ध का संक्षिप्त इतिहास

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन युद्ध के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में 180 डिग्री का बदलाव किया है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- यूक्रेन के राष्ट्रपित वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच ओवल ऑिफस में सार्वजिनक असहमित हुई, जिसके कारण अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता रोक दी।
- एक दिन के भीतर ही ज़ेलेंस्की ने स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए ट्रम्प के साथ आंशिक युद्धविराम और सहयोग के लिए कीव की इच्छा की घोषणा की।

युद्ध की उत्पत्ति -

- 24 फरवरी, 2022: रूसी राष्ट्रपित व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया, उन्हें जल्दी जीत की उम्मीद थी।
- अमेरिका सिहत पश्चिमी देशों ने शुरू में यूक्रेन के पतन का अनुमान लगाया था, इसलिए उन्होंने कीव से अपने द्वतावासों को खाली कर दिया।
- हालांकि, अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों के समर्थन से यूक्रेन के प्रतिरोध ने रूस की शुरुआती जीत को रोक दिया।
- बाईडेन प्रशासन ने दो-आयामी रणनीति अपनाई:
 - रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए गए।
 - रूस से लंडने के लिए यूक्रेन को भारी सैन्य सहायता।
- रूसी असफलताएँ:
 - सितंबर 2022: रूस उत्तर-पूर्व में खार्किव ओब्लास्ट से पीछे हट गया।
 - नवंबर 2022: रूसी सेनाएँ खेरसॉन शहर और दक्षिण में मायकोलाइव के कुछ हिस्सों से पीछे हट गईं।
- रूस की जवाबी रणनीति:
 - चार यूक्रेनी ओब्लास्ट (डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया, खेरसॉन) पर कब्ज़ा किया।
 - एक लंबे युद्ध की तैयारी के लिए सैनिकों की आंशिक लामबंदी।
 - एशिया की ओर आर्थिक धुरी, पश्चिमी प्रतिबंधों को दरिकनार करने के लिए चीन और भारत के बाजारों का लाभ उठाना।





युद्ध की वर्तमान स्थिति (2023-2025)

- 2023: रूस ने खोई हुई ज़मीन वापस हासिल करना शुरू कर दिया, प्रमुख स्थानों को सुरक्षित किया:
 - सोलेडर (जनवरी 2023)
 - बखमुट (मई 2023)
- 2024: रूसी सेना ने कब्जा किया:
 - अव्दिक्ना (फरवरी 20<mark>24)</mark>
 - क्रास्नोहोरिक्का (सितंबर 2024)
 - वुहलदार (अक्टूबर 2024)
- यूक्रेनी जवाबी हमला (जून 2023): उन्नत पश्चिमी हथियारों के साथ शुरू किया गया लेकिन रूस की मजबूत सरक्षा के सामने विफल रहा।
- अगस्त 2024: यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक हमला किया, और पूर्व में रूसी प्रगति पर दबाव बनाने के लिए 1,000 वर्ग किमी पर कब्जा कर लिया।
- RUSSIA 5km 2 miles UKRAINE Pokrovsk Selidove Avdiivka Krasnohorivka Kurakhove Donetsk Russian military control Claimed Russian control Limited Russian military control ☐ Russia annexed Crimea in 2014 Limit of Ukrainian advance Source: ISW (21:00 GMT, 3 March) ВВС

• रूस का जवाबी हमला:

- कुर्स्क हमले को नज़रअंदाज़ किया और यूक्रेन की पूर्वी कमज़ोरियों पर ध्यान केंद्रित किया।
- 2024 तक, रूस ने यूक्रेन और रूस के कुर्स्क क्षेत्र दोनों में 4,168 वर्ग किमी पर कब्ज़ा कर लिया था।
- जनवरी 2025: रूसी सैनिकों द्वारा कब्ज़ा:
 - वेलिका नोवोसिल्का



- टोरेत्स्क के कुछ भागपोक्रोवस्क को घेरने का प्रयास
- यूक्रेन की रणनीति:
 - रूस के अन्दर और काला सागर में ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए गए।
 हालाँकि, दो साल से अधिक समय तक सैन्य दृष्टि से पिछड़ा रहा।

पहलू	यूरोपीय परिप्रेक्ष्य	अमेरिकी परिप्रेक्ष्य
युद्ध पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया	यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन तनाव बढ़ाने को लेकर झिझक थी; रूस पर ऊर्जा निर्भरता को लेकर आर्थिक चिंताएं थीं।	दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया गया: रूस पर प्रतिबंध और यूक्रेन को सैन्य सहायता।
सैन्य सहायता	यूरोपीय देशों ने सैन्य सहायता तो प्रदान की, लेकिन दीर्घकालिक स्वतंत्र सहायता की क्षमता का अभाव था।	उन्नत हथियार, खुफिया जानकारी और वित्तीय सहायता प्रदान की।
आर्थिक लागत और चुनौतियाँ	रूसी गैस की हानि (नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन तोड़फोड़) के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे जीवन-यापन की लागत में संकट और विऔद्योगीकरण की स्थिति पैदा हो गई।	युद्ध से अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक अप्रभावित रही, जिससे उसे सैन्य सहायता जारी रखने में मदद मिली।
यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता	2008 में शुरू में इसमें हिचिकचाहट थी (फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया था)। अब, सुरक्षा गारंटी चाहता है लेकिन इसे कैसे प्रदान किया जाए, इस पर आम सहमति नहीं है।	शुरू में यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता का समर्थन किया गया था, लेकिन ट्रम्प के अधीन, इसे छोड़ दिया गया और सुरक्षा गारंटी से इनकार कर दिया गया।
सुरक्षा चिंताएं	रूस के विस्तारवाद से डर लगता है, लेकिन नाटों में अमेरिकी नेतृत्व के बिना एकीकृत रक्षा रणनीति का अभाव है।	रणनीतिक बदलाव को प्राथमिकता देते हुए चीन को रूस के बजाय बड़ा खतरा माना गया है।
ट्रम्प के अधीन नीतिगत बदलाव	अमेरिका के अचानक पलटवार से अचंभित होकर, अब संघर्ष में अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने में जुट गया है।	ट्रम्प के नेतृत्व में रूस के साथ पुनः गठबंधन की ओर रुख किया गया तथा यूक्रेन के हितों की अपेक्षा महाशक्ति राजनीति पर अधिक ध्यान दिया गया।
दीर्घकालिक रणनीति	रूस के विरुद्ध निरन्तर प्रतिरोध चाहता है, लेकिन उसके पास स्वतंत्र सैन्य शक्ति का अभाव है।	इसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करके तथा चीन-रूस गठबंधन को रोककर वैश्विक रणनीति को पुनः निर्धारित करना है।



प्रमुख चुनौतियाँ	युद्ध से नियंत्रित निकास सुनिश्चित करते हुए रूस और चीन दोनों के साथ संबंधों का प्रबंधन करना।

यूक्रेन की स्थिति -

• भारी नुकसान:

- अपना 20% से अधिक क्षेत्र खो दिया।
- हजारों सैनिक मारे गये।
- लाखों यूक्रेनवासी विस्थापित हुए।

• अर्थव्यवस्था ढहं जानाः

- ० रूसी बमबारी से बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा।
- बाहरी सैन्य आपूर्ति (तोपखाना, गोला-बारूद, हथियार) पर निर्भर।
- युद्ध के मैदान में जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

• अंधकारमय भविष्यः

- अमेरिका द्वारा समर्थन वापस लेने से यूक्रेन की जीत लगभग असंभव हो जाएगी।
- कोई नाटो सदस्यता या सुरक्षा गारंटी नहीं।
- युद्ध जारी रखने से अधिक क्षेत्रीय क्षित का खतरा है।
- o युद्ध को रोकने का मतलब है रूस और अमेरिका द्वारा तय किए गए समझौते को स्वीकार करना

अंतिम विश्लेषणः

- महाशक्तियाँ अपने सामिरक हितों के लिए छद्म युद्धों का उपयोग करती हैं।
- जब उनके हित संरेखित हो जाते हैं तो वे संबंधों को पुनः स्थापित कर लेते हैं।
- यूक्रेन के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं बचा है, जो इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि वैश्विक शक्ति संघर्ष में प्रॉक्सी को किस प्रकार कष्ट उठाना पड़ता है।

स्रोत: The Hindu: A brief history of the Russia-Ukraine war